जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 79 दिनांक:22-07-2024 सोमवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह किसी भी मुद्दे पर सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

विश्व धरोहर समिति के 10 दिन चलने वाले 46वें सत्र का शुभारंभ हो गया है। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भारत मंडपम में बैठक का उद्घाटन किया।

संसद का मानसून सत्र आज से, ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा

नीट और कांवड़ यात्रा पर हंगामे के आसार

नई दिल्ली(ईएमएस)। लोकसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नीट फर्जीवाड़ा और कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने का मुद्दा गरमाएगा। इसका संकेत विपक्ष ने सर्वेदलीय बैठक में दे दिया है। संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले रविवार को पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मुद्दा उठाया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वायएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश, आप सांसद संजय सिंह, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसमें नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सर्वदलीय बैठक मानसून सत्र के दौरान संसद अच्छे से चलाने के लिए बुलाई जाती है। विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए संसद में हंगामा होता है और सत्र ठीक से नहीं चल पाता।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी है और संविधान, उसके मूल्यों और परंपराओं की हत्या कर रही है। जिस तरह से संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को यहां से हटाया गया है, जिस तरह से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही है, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं और यह सरकार इन सबको कायरता के साथ तरह देख रही है, जिस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान का अनादर किया जा रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हैं। हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे।

10 वर्षों से संसद में ठीक से काम नहीं हुआ

सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद को ठीक से काम करना चाहिए और बहस और चर्चा होनी चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जमीनी हकीकत को समझे। बेरोजगारी दर अपने चरम पर है, लोग भूख से मर रहे हैं। राज्यों की शक्ति पर हमला हुआ है।

बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कांवड़ यात्रा और नीट का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कांवड़ यात्रा और नीट पेपर लीक मामले का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश सहित कई नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष से उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दबाव डाला। सूत्रों के मुताबिक, सर्वदलीय बैठक में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है।

इसके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड) और बीजू जनता दल (बीजेडी) ने क्रमश: आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरजोर वकालत की।

संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार के द्वारा छह विधेयक पेश करने की उम्मीद है, जिसमें 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। साथ ही इस सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी, जो केंद्रीय शासन के अधीन है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण और मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ तैनात

यूपी में 24 घंटे में 11 की मौत, मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक डूबा, लखीमपुर में हाईवे पर आई बाढ़ में बह गई मैजिक, गोंडा में गर्दन तक भरा घाघरा का पानी, मप्र में पहली बार सीजन में किसी बांध के गेट खुले

सतपुड़ा बांध के 11 गेट खुले,पचमढ़ी में लैंड स्लाइड

नई दिल्ली(ईएमएस)। देशभर में मानसून की बारिश हो रही है। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात की गई हैं। मप्र में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। बैतूल के सारणी में 9 इंच बारिश हुई। रविवार सुबह यहां के सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदापुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पचमढ़ी में लैंड स्लाइड से पहाड़ से सटा रास्ता बंद हो गया। माखननगर के झालसर गांव में सुबह 5 बजे मकान की दीवार गिर गई। दबने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई।

यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां यहां उफान पर है। पानी हाईवे तक पहुंच गया। बाढ़ के पानी में मैजिक बह गई। मुरादाबाद में रविवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में एक से दो फीट तक पानी भर गया। रेलवे ट्रैक डूब गया। इससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा। गोंडा में घाघरा खतरे के निशान के 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे गांवों में गर्दन तक पानी भर गया है। गोरखपुर में राप्ती एक हफ्ते से खतरे के निशान के ऊपर बह रही। 55 गांव डूब गए हैं। 30 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों को ऊंची जगहों पर रेस्क्यू होने की अपील कर रहा है।

प्रदेश में 1.1 इंच बारिश कम

प्रदेश में 21 जून से मानसून ने आमद दे दी थी। इसके बाद से ही तेज बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि, पूर्वी हिस्से में अभी सूखा जैसा है। यहां 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में 2 प्रतिशत बारिश ज्यादा है। ओवरऑल बात करें तो अब तक 9 प्रतिशत बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, अब तक एवरेज 12.7 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इसके मुकाबले 11.6 इंच बारिश ही हुई है।

बालाघाट में हाईवे पर बह रहा पानी

बालाघाट में शनिवार रात से बारिश हो रही है। यहां कंजई नाला उफान पर है। पानी सिवनी स्टेट हाईवे पर से बह रहा है, जिससे दो तरफ का ट्रैफिक रुक गया है। नर्मदापुरम में शनिवार रात से हो रही तेज बारिश से कॉलोनियों में खड़ी कारों की छतों तक पानी भर गया। इटारसी रेलवे स्टेशन के पास बने जीआरपी थाने में पानी भर गया।

सीहोर में घरों में रखा अनाज भीगा

सीहोर के लाडक़ुई में कई फीट तक पानी भर गया है। घरों में रखा अनाज भीग गया। यहां रविवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। एक शख्स ने अपने घर का वीडियो बनाया, जिसमें वह बता रहा है कि उसके घर में रखा अनाज खराब हो गया है। मूंग, उड़द और सोयाबीन भीग गए, जिससे करीब डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सीहोर जिले के बुधनी में भारी बारिश जारी है।यहां दुकानों में पानी भर गया है।

पचमढ़ी में बारिश से पहाड़ धंसा

पचमढ़ी में बारिश से पहाड़ धसक गया। पहाड़ से सटे रास्ते में मलबा आ गया, जिससे ट्रैफिक रुक गया है। धूपगढ़ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। शनिवार रात पचमढ़ी में साढ़े 4 इंच पानी गिरा। नर्मदापुरम जिले के माखननगर के झालसर गांव में रविवार सुबह 5 बजे बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई। मां और उसकी तीन साल की बच्ची दब गए। बच्ची गरिमा मुकेश की मौत हो गई। मां को बुधनी के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नर्मदापुरम के इटारसी में कमर तक भरा पानी

नर्मदापुरम के इटारसी में मेहरागांव नदी उफान पर है। नदी का पानी भर जाने से इटारसी-न्यूयार्ड मार्ग भी बंद हो गया है। रविवार को इटारसी में 168.4 एमएम बारिश दर्ज की गई। शहर के अंडर ब्रिज में कमर तक पानी भर गया है।

डूबा लखनवाड़ा घाट व पुराना पुल

झमाझम बारिश से वैनगंगा नदी उफान पर है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले के बरघाट विकासखंड में सर्वाधिक 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। वैनगंगा नदी के उफान में होने से कई रपटों व छोटे पुल से आवागमन अवरुद्ध है। जोरदार वर्षा से इस सीजन में पहली बार वैनगंगा नदी का लखनवाड़ा घाट व छोटा पुल सहित घाट पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं।

डेढ़ मीटर बढ़ा संजय सरोवर बांध का लेवल

वैनगंगा नदी पर बने संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में पहुंचने से बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बांध का जल स्तर रविवार दोपहर तक 516.90 मीटर हो गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पानी की आवक में शाम तक इजाफा होने पर बांध के गेट खोलने का निर्णय लिया जाएगा।

हरियाणा के नूंह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा में कड़े सुरक्षा इंतजाम

नई दिल्ली (ईएमएस)। हरियाणा के नूंह में सोमवार को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कई कदम उठाए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, आज शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आसमान से जमीन तक पैनी नजर रखी जाएगी। नूंह पुलिस ने भारी वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाईजरी भी जारी की है।

नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह विभाग ने 21 जुलाई शाम 6 बजे से 22 जुलाई शाम 6 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान बल्क मैसेज सेवाओं पर भी रोक रहेगी।

गृह विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 2000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के जवानों को तैनात किया है। साथ ही ड्रोन से यात्रा की निगरानी की जाएगी।

साथ ही अरावली पर्वत में भी हरियाणा पुलिस के कमांडो द्वारा सर्च अभियान चलाया जाएगा और डॉग स्क्वॉयड के अलावा घोड़ा पुलिस भी जिले के अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहेगी। साथ ही नूंह पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जिन भारी वाहनों को पलवल, होडल व अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) से नूंह जाना हैं, वो ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा समाप्त होने के बाद ही नूंह आएं। वहीं जिन भारी वाहनों को जयपुर से नूंह आना हैं उनके लिए मुम्बई एक्सप्रेस-वे से केएमपी रेवासन होते हुए यात्रा समाप्त होने के बाद नूंह आने की एडवाइजरी जारी की गई है।

नूंह पुलिस ने पुन्हाना से नूंह, गुरुग्राम से नूंह और तावडू से नूंह आने वाले भारी वाहनों को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा समाप्त के बाद ही नूंह आने के लिए कहा है। एडवाइजरी के मुताबिक, ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भारी वाहनों का नूंह जिले में प्रवेश वर्जित रहेगा।

ज्ञात रहे कि पिछले साल ब्रज मंडल यात्रा के दौरान नूंह में बवाल हो गया था। 31 जुलाई को भड़की हिंसा में दो होमगार्ड सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह हिंसा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई थी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नेमप्लेट विवाद

योगी सरकार के आदेश को दी गई चुनौती, आज सुनवाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पडऩे वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है।

सोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पडऩे वाले भोजनालयों, ढाबों, फलों की दुकानों और चाय की दुकानों को मालिकों के विवरण बताने वाली नेमप्लेट प्रदर्शित करने के लिए कहा है। इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया है और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है।

कुछ चुनिंदा सेंटरों से नहीं बल्कि पूरे देश से छात्रों ने नीट-यूजी की परीक्षा पास की - सरकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। नीट-यूजी के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिजल्ट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि हर बार से अलग देश के कुछ चुनिंदा सेंटरों से नहीं बल्कि पूरे देश से छात्रों ने नीट-यूजी की परीक्षा पास की है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिकनीट 2024 में कुल 23।33 लाख छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 2321 छात्रों को 700 या इससे अधिक अंक मिले हैं।

यह छात्र पूरे देश और विदेश में 1,404 केंद्रों में फैले हुए थे। यह 1404 केंद्र 276 शहरों और 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में थे। इतना बड़ा फैलाव दर्शाता है कि बहुत सारे छात्रों के नंबर आए हैं, जो कि कोचिंग सेंटरों वाले शहरों से नहीं थे। वे भी नीट 2024 में टॉपर्स की सूची में आने में सक्षम थे।

सरकार ने यह माना है कि यह सच है कि सीकर, कोटा और कोट्टायम जैसे पारंपरिक टयूशन हब से आने वाले कई छात्र 700 या उससे अधिक अंक लाए हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि अन्य शहरों से आने वाले कई छात्र भी इस ब्रैकेट में आने में सक्षम थे।

उदाहरण के लिए लखनऊ से 35 छात्र, कोलकाता से 27 छात्र, लातूर से 25 छात्र, नागपुर से 20 छात्र, फरीदाबाद से 19, नांदेड़ से 18, इंदौर से 17, कटक और कानपुर से 16-16, कोल्हापुर, नोएडा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से 14-14, आगरा और अलीगढ़ से 13-13, अकोला और पटियाला से 10-10, दावणगेरे से 8, बनासकांठा से 7 छात्र 700 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहे।

सरकार ने कहा है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि नीट के पाठयक्रम को उच्चतर माध्यमिक के पाठयक्रम के साथ जोड़ने से यह परिणाम मिलने लगे हैं।

मुश्किल में मोदी की मंत्री! कांग्रेस ने चुनाव शून्य घोषित कराने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

धार(ईएमएस)। जिले से सांसद चुनी गईं मोदी सरकार में राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह ये है कि कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस ने तमाम तर्क रखते हुए अपनी याचिका में चुनाव को शून्य कराने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मुवैल ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि सावित्री ठाकुर ने अपनी आय संबंधी जानकारियों को छिपाया है। सावित्री ठाकुर, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री हैं, पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में अपनी आय संबंधी गलत जानकारी दी और कुछ जानकारियां दी ही नहीं। राधेश्याम मुवैल, जो धार संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे, ने आरोप लगाया है कि शपथ पत्र में कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। उन्होंने इस आधार पर धार के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों?

- दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले में अब बाबा रामदेव भी कूदे

हरिद्वार,(ईएमएस)। यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ तीर्थयात्रियों की आस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी फलों की दुकानों, भोजनालयों, रेस्टोरेंट के मालिकों की नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों इसे बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति बताया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का पूरा हक है, जैसे अन्य धर्मों के लोगों को। अब इस मामले में योग गुरु बाबा रामदेव भी कूद पड़े हैं।

रामदेव ने कहा है कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अपने नाम पर सबको गर्व होता है। नाम छिपाने की जरूरत नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए बस। बता दें कि यूपी सरकार के इस पहल के बाद, उत्तराखंड ने नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। यूपी सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्तराखंड पुलिस ने नेमप्लेट लगाने से संबंधित नियमों का नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विपक्षी दलों ने इस कदम को प्रायोजित कट्टरता और मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करने वाली कार्रवाई बताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। सरकार शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहती है। वहीं यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की योगी सरकार ने चुनावी लाभ के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना पूरा नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है।

कांग्रेस की यूपी इकाई के प्रमुख अजय राय ने फैसले की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी सरकार लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की है।

रीवा में दो महिलाओं को जिंदा गाड़ा

-निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध करना पड़ा महंगा

रीवा,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीनी विवाद के चलते दंबगों ने दो महिलाओं को जिंदा गाड़ने जैसा दुस्साहस कर दिया। यह तो भला हो कि समय रहते दोनों महिलाओं को मुरम से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पीड़ित महिलाओं की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

जानकारी अनुसार रीवा जिले के हिनौवा गांव में एक निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। उनकी जमीन पर सड़क बनाए जाने का विरोध महिलाएं कर रही थीं। इसी दौरान दंबगों ने दोनों महिलाओं के ऊपर सड़क निर्माण में इस्तेमाल में आने वाली मुरुम डाल दी, जिससे एक महिला गले तक और दूसरी महिला कमर के ऊपर तक मिट्टी में धंस गईं। बताया जा रहा है कि राजेश सिंह उर्फ छुटकउ अपनी जेसीबी और मुरुम से भरा डंपर लेकर विवादित स्थल पर सड़क बनाने के लिए पहुंचा था। निजी जमीन पर सड़क बनते देख आशा पांडेय और ममता पांडेय ने विरोध किया। दोनों महिलाओं द्वारा किए जा रहे विरोध से नाराज दूसरे पक्ष के गोकर्ण पांडेय, महेंद्र पांडेय, चंद्रभान पांडेय सहित आधे दर्जन से ज्यादा लोगों ने दोनों महिलाओं के साथ मारपीट कर दी। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने दोनों महिलाओं के ऊपर डंपर से मुरुम उड़ेल दिया। इससे एक महिला गले तक जबकि दूसरी महिला कमर तक मुरम में धंस गई। विवाद होने की जानकारी मिलने पर दोनों महिलाओं के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और फावड़े की मदद से मुरम में धंसीं दोनों महिलाओं को बाहर निकाला।

इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। गंगेव पुलिस चौकी ने डंपर मालिक समेत मारपीट करने वाले अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लीया है। दोनों ही महिलाओं का इलाज करवाया गया है, जिसके बाद हालत ठीक होना बताया है।

निपाह वायरस से नाबालिग ने तोड़ा दम

तिरुवनंतपुरम (ईएमएस)। केरल में निपाह वायरस ने एक और जान ले ली। मल्लपुरम जिले में निपाह वायरस से संक्रमित मिले 14 वर्षीय लडक़े की रविवार को निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह वेंटिलेटर पर था। इसके बाद सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं नाबालिग के संपर्क में आए लोगों के बचाव के लिए केरल ने पुणे एनआईवी से आस्ट्रेलिया से खरीदी गई मोनाक्लोनल एंटीबॉडी मंगाई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि निजी अस्पताल में निपाह वायरस का इलाज करा रहे बालक की मौत हो गई। केरल में सितंबर 2023 के बाद इस संक्रमण का मामला फिर से सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बालक 12 मई को निजी क्लीनिक में इलाज कराने पहुंचा था। 15 मई को उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे पेरिंथलमन्ना के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां भी ठीक न होने पर बालक को कोझिकोड के निजी अस्पताल में भेजा गया।

अब उज्जैन में दुकान के बाहर लगानी होगी नेमप्लेट नहीं तो भरना होगा जुर्माना

भोपाल (ईएमएस)। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखी नेमप्लेट लगाने के फैसले का असर अब मध्यप्रदेश में दिखने लगा है। यहां भी इसी तरह के फैसले की मांग उठने लगी है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में भी इसी तरह का फैसला लिया जा सकता है। उज्जैन में शनिवार को दुकान मालिकों को अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर की प्लेट लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

बीजेपी के दो विधायक रमेश मेंदोला और मालिनी गोड़ ने तो सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर दुकान मालिकों का नाम दुकान के बाहर दर्ज करने को अनिवार्य किए जाने की मांग की है। जबलपुर के विधायक अशोक रोहाणी ने भी खान-पान व फलों की दुकानों के बाहर दुकान मालिक का नाम लिखने का समर्थन किया है। राज्य में उज्जैन ऐसा नगर है, जहां नगर निगम ने करीब एक साल पहले दुकानों के बाहर मालिक की नाम पट्टिका लगाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश पर अमल नहीं हुआ है।

अब नगर निगम ने दुकानदारों को एक बार फिर हिदायत देते हुए दुकान के बाहर नेमप्लेट न लगाने की बात कही है नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार भी यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर फैसला करने को लेकर मंथन कर रही है। आगामी दिनों में भी कोई फैसला ले सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने को सख्त बताने के साथ ही अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ऐसे कई फैसले ले रहे हैं। इसलिए इस बात की संभावना है कि प्रदेश में दुकान के बाहर मालिकों की नेमप्लेट लगाने का फैसला लिया जा सकता है।

भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दोगुनी होने की संभावना

नई दिल्ली (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कहा है कि भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दोगुनी हो जाने की संभावना है। देश में खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है, जिनके अकेले रह जाने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है। 'यूएनएफपीए-इंडिया की 'रेजिडेंट प्रतिनिधि वोजनार ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जनसंख्या के उन प्रमुख रुझानों को रेखांकित किया, जिन्हें भारत सतत विकास में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता दे रहा है। इनमें युवा आबादी, वृद्ध जनसंख्या, शहरीकरण, प्रवासन और जलवायु के अनुसार बदलाव करना शामिल हैं। ये कारक सभी देश के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर पेश करते हैं।

वोजनार ने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 34 करोड़ 60 लाख हो जाने का अनुमान है, इसलिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

'यूएनएफपीए-इंडिया प्रमुख ने कहा कि भारत में युवा आबादी काफी है और 10 से 19 वर्ष की आयु के 25 करोड़ 20 लाख लोग हैं। भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दोगुनी हो जाने की संभावना है।

उन्होंने जिक्र किया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सृजन में निवेश करने से इस जनसांख्यिकीय क्षमता को भुनाया जा सकता है और देश को सतत प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

उप्र में सत्ता और संगठन के बीच जारी घमासान का समाधान 27 को होगा?

लखनऊ(ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान बढ़ा है। यहां सत्ता और संगठन के बीच शुरु हुई तनातनी फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्या ने संगठन को बड़ा बताकर सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे दी है। इस बीच कई नेताओं ने भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात कर अपनी बात रखने की खबरें भी आई। लेकिन समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया है। अब 27 जुलाई को

नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि यहां उप्र की सियासी समस्या का समाधान निकल आएगा।

लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी भाजपा के भीतर चल रहे कलह की पृष्ठभूमि में ये प्रस्तावित बैठकें महत्वपूर्ण हैं, जो 14 जुलाई को लखनऊ में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद और भी गंभीर हो गई है। सूत्रों ने कहा कि योगी से सरकार के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा करने की उम्मीद है। दिल्ली में सीएम की निर्धारित बैठक 29 जुलाई से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले हो रही है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री से विपक्ष, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है, जिसने लोकसभा चुनाव में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद अपनी पूरी आक्रामकता वापस पा ली है।

सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष सूत्र का दावा है कि भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों की टीम को टास्क दिए गए हैं। यह इस टीम के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, जिसका नेतृत्व खुद सीएम करेंगे। राज्य सरकार और पार्टी संगठन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों, मुख्य रूप से पार्टी विधायकों और सांसदों का मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि योगी सरकार ने विधायकों को सरकार और पार्टी के खिलाफ बोलने की संभावना को रोकने के लिए चिंतित विधायकों को शांत करने का फैसला किया है।

राजनीतिक हलकों में सरकार बनाम संगठन की बहस तब चर्चा में आई जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राज्य कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसे सीएम योगी पर निशाना साधते हुए देखा गया। सीएम योगी ने बाद में उसी बैठक में कहा कि अति आत्मविश्वास यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन का कारण था। यूपी बीजेपी के भीतर कलह की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर तब गूंजी, जब इस बैठक के ठीक तीन दिन बाद केशव

जन हितैषी

माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर बंद होने से हजारों करोड़ का नुकसान

माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर शुक्रवार को कुछ देर बंद रहा। पूरी दुनिया के देशों में अफरा-तफरी मच गई। 1 घंटे के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक को 73000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। शेयर बाजार मैं कंपनी के शेयर में 8 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। देखते ही देखते कंपनी के 73000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गए। एयरपोर्ट, रेल, बैंक, शेयर बाजार में मची अफरा-तफरी के कारण बैंकों, शेयर बाजार, कारोबारी कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। यात्रियों को काफी कष्ट उठाना पड़ा। बैंक के ग्राहक भी कई घंटों तक परेशान होते रहे। सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक के 30000 से अधिक ग्राहक हैं। क्राउड स्ट्राइक कंपनी 30000 से अधिक कंपनियों को साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराती थी। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बंद हुआ। उसके बाद सारी दुनिया में हाहाकार मच गया था। यूरोपीय देशों में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। भारत में नुकसान हुआ लेकिन यह नुकसान यूरोपीय देशों की तुलना में कम था। क्योंकि यूरोपीय देशों की तरह भारत अभी पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं हुआ है। इसलिए बहुत हद तक बचा रहा। यूरोपीय देशों में सब कुछ ऑनलाइन था, जिसके कारण यात्रियों, बैंक के ग्राहकों और शेयर बाजार के निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। क्राउड स्ट्राइक कंपनी और उससे जुड़ी हुई अन्य कंपनियों के यदि नुकसान को देखा जाए तो यह लाखों करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। यह आर्थिक नुकसान की बात हुई। 15 घंटे तक सारी दुनिया के देशों मे ऑनलाइन सर्विस के कारण ऑनलाइन सेवा नहीं दे पाए। उसके कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल और ऑनलाइन कारोबार में एकाधिकार है। अपरोक्ष रूप से हार्डवेयर पर भी माइक्रोसॉफ्ट का एकाधिकार है। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर चुनिंदा हार्डवेयर पर ही संचालित होते हैं। इस एकाधिकार के कारण और कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से, ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया ठहर गई है। थोड़ी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण सर्वर क्रैश हो जाना है। जैसे-जैसे सारी दुनिया तकनीकी के सहारे आगे बढ़ रही है। सारे काम डिजिटल प्रोग्रामिंग से संचालित हो रहे हैं। यदि 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर बंद हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी से जुड़े हुए कंपनियों के लाखों सर्वर एकाएक बंद हो गए। सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को सेवा मिलना बंद हो गई। जिस तरह से अब ए-आई तकनीकी आ गई है। सारे काम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग से संचालित हो रहे हैं। अब जगह-जगह रोबोट भी इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी से जुड़कर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है। हमारे जीवन में जिस तरह से तकनीकी का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। मानवीय चूक का अब कोई कारण नहीं है। अब जो भी चूक हो रही है। वह सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, तकनीकी तथा संचार माध्यमों के कारण हो रही है। जिन पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। तकनीकी अथवा संचार की गड़बड़ी से कभी भी कहीं पर भी कोई भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। पिछले दो दशक में सुरक्षा, कारोबार, घर, व्यापारिक स्थलों के कामों में डिजिटल तकनीकी और संचार माध्यमों पर आश्रित होकर रह गए हैं। अब मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के जरिए एक स्थान से सारी दुनिया में कंट्रोल कर रहे हैं। जब कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तब क्या स्थिति होगी। इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। क्राउड स्ट्राइक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जब अपनी ही रक्षा नहीं कर पाई। वह उससे जुड़ी हुई 30000 कंपनियों के सर्वर और सॉफ्टवेयर की क्या सुरक्षा कर पाएगी। इसे आसानी से समझा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एकाधिकार बना लिया है। यदि उसके प्रोग्राम कहीं क्रश होते हैं, तो इसका कितना बड़ा नुकसान सारी दुनिया को हो सकता है। इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। शुक्रवार की एक घटना ने सारी दुनिया को एक तरह से चेतावनी दे दी है। तकनीकी के ऊपर आश्रित होकर मानवीय विकास एवं मानव क्षमता का सही उपयोग नहीं किया गया, तो कभी भी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भारत जैसे देश में जिस तरह से यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान, अधिकतम सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरवर में रखा हुआ डाटा यदि हैक हो जाता है। साइबर ठग उसका दुरुपयोग कर ठगी करते हैं। पिछले वर्षों में भारत जैसे देश में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी होने लगी है। तकनीकी कारणों से यदि डाटा तक पहुंच नहीं हो पाती है। डाटा हैक हो जाता है। डाटा को प्रोग्रामिंग के द्वारा बदल दिया जाता है। तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। भारत जैसे देश के पास इंटरनेट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इंटरनेट के साथ-साथ इंटरानेट पर भी काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपना संचार माध्यम विकसित किया है। जिस पर उनका स्वयं का कंट्रोल है। राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने अलग व्यवस्था बना रखी है। जिन देशों के पास इंटरानेट आधारित संचार नेटवर्क है। उन्होंने डाटा को कई स्तर पर स्टोर करके रखा हुआ है। उन देशों के पास एक अच्छा विकल्प होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दुनिया के वह देश जो केवल माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेट पर आधारित होकर रह गए हैं। वह कभी भी तकनीकी की इस दौड़ में डूब सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कुछ ही घंटे में तकनीकी के कारण हो सकता है। जान-माल का नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता है। जिसकी कल्पना संभव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो गड़बड़ी आई। प्रोग्रामिंग के जरिए मशीनों के द्वारा मशीनों को चलाने की जो नई तकनीकी विकसित हुई है। आगे चलकर उसके दुष्परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं। समय रहते भारत सहित दुनिया के सभी देशों को विकल्प के बारे में ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सेवाओं को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग प्रोग्रामिंग के जरिए नियंत्रण करने की व्यवस्था बनानी होगी। तकनीकी में एकाधिकार से भी बचना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भगवान ही मालिक है।

भारत में तेजी से हो रहा है वित्तीय समावेशन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैकिंग, निवेश, बीमा, डाक एवं पेन्शन क्षेत्र के हितधारकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया है। दरअसल, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतुलनीय प्रगति को दर्शाने के लिए अब अपने सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत विदेशी संस्थानों द्वारा विकसित किए गए सूचकांकों के आधार पर किए जाने वाले सर्वे में तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रभावशाली प्रगति की सही तस्वीर पेश नहीं की जा रही है। इन सूचकांकों के आधार पर किए गए कई सर्वे में तो आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे, एक सर्वे में भुखमरी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश से भी बदतर बताया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक के आधार पर मार्च 2024 के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार, भारत में वित्तीय समावेशन मार्च 2017 में 43.4, मार्च 2021 में 53.9 एवं मार्च 2023 में 60.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 प्रतिशत हो गया है। यह सूचकांक भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई अतुलनीय एवं स्थिर प्रगति को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों (नागरिकों की वित्तीय संस्थानों पर बढ़ती पहुंच, वित्तीय उत्पादों का बढ़ता उपयोग एवं वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता) पर देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जानकारी को 0 से 100 तक के मान में बताता है। यदि मान कम है तो देश में वित्तीय समावेशन भी कम है और इसके विपरीत यदि मान अधिक है तो देश में वित्तीय समावेशन भी अधिक है। भारत में यह मान मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 प्रतिशत हो गया है। उक्त वर्णित तीन आयामों में कई पैरामीटर शामिल हैं, इनका मूल्यांकन 97 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इस कार्यप्रणाली के कारण ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन का एक व्यापक संकेतक बन गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

किसी भी देश में वित्तीय समावेशन के बढ़ने का आशय यह है कि उस देश के नागरिकों की उस देश के बैकिंग संस्थानों तक पहुंच बढ़ रही है और यह उस देश की अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। वर्ष 2014 में भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैकों में गरीब वर्ग के जमा खाते खोलकर उन्हें वित्तीय समावेशन का हिस्सा बना लिया गया था। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं एवं इन जमा खातों में लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के गरीब वर्ग को दी जाने वाली सहायता/प्रोत्साहन राशि को भी इन खातों में आज सीधे ही जमा कर दिया जाता है, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि इससे अंततः लीकेज कम हुए है और यह सुनिश्चित हुआ है कि योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक सीधे ही पहुंचे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज के इलाकों में निवासरत नागरिकों को बैंकिंग, बचत और जमा खाते, राशि हस्तांतरण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जनधन योजना पूर्ण रूप से सफल रही है और भारत में वित्तीय समावेशन को अगले स्तर पर ले जाने में भी सहायक रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए जमा खातों को भारत की विशिष्ट पहचान प्रणाली (आधार कार्ड) से जोड़कर, केंद्र सरकार ने देश में वित्तीय लेन देन प्रणाली को सुव्यवस्थित कर लिया है एवं बैकिंग व्यवहारों में धोखाधड़ी की सम्भावना को कम करने में भी सफलता अर्जित की है। आज भारत की प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना के रूप में पहिचान मिली है।

देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज भी वित्तीय समावेशन के मुख्य उपकरण के रूप में माना जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों के खाते विभिन्न बैंकों में उसी उत्साह से लगातार खोले जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी भारत के विभिन्न बैकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 3.3 करोड़ नए जमा खाते खोले गए हैं इससे इस योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या बढ़कर 51.95 करोड़ हो गई है एवं इन जमा खातों में 234,997 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। अब देश का एक गरीब नागरिक भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्तीय समावेशन के दायरे में लाए गए नागरिक वित्तीय क्षेत्र में साक्षर होने के पश्चात अब तो भारत के पूंजी बाजार (शेयर बाजार) में भी अपना निवेश करने लगे हैं एवं उनकी विभिन्न ऋण योजनाओं एवं बीमा उत्पादों तक पहुंच भी बढ़ गई है। वित्तीय सेवाओं तक इस पहुंच ने देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बना दिया है, इससे अंततः यह नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं छोटे व्यवसायों में निवेश करने में सक्षम हुए हैं और इस प्रकार इन नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई उक्त वर्णित अतुलनीय प्रगति की जानकारी हम आम नागरिकों को तभी मिल पा रही है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में ही एक सूचकांक विकसित किया है। यदि वित्तीय समावेशन का सूचकांक किसी विदेशी संस्थान द्वारा तैयार किया जाता तो सम्भव है कि भारत की इस महान उपलब्धि को जानने से हम वंचित रह जाते। अब समय आ गया है कि इसी प्रकार के सूचकांक अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों द्वारा ही तैयार किए जाने चाहिए, ताकि हम आम नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत की अतुलनीय प्रगति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके। (लेखक- प्रहलाद सबनानी / ईएमएस)

यह है नफरत की राजनीति और सांप्रदायिकता का शोकगीत

क्या 2024 के लोक सभा चुनाव स्वतंत्र भारत के राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करने तथा एकता, न्याय और प्रगति के सिद्धांतों पर आधारित समाज को प्राथमिकता देने का संकेत दिया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय मतदाताओं ने राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णायक योगदान दिया है और गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी जैसे व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। चुनाव परिणामों ने पिछली भाजपा नीत सरकार की नफरत की राजनीति, विपक्ष को दबाने के लिए संवैधानिक एजेंसियों के इस्तेमाल और बड़े व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भेजा है, जो असमान विकास और बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं।

542 सदस्यों वाले सदन में 243 सीटें हासिल करके, ष्ठ्रश्ँ गठबंधन की जीत का श्रेय किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और नागरिक समाज के समर्थन को दिया जाता है। विपक्षी दलों को अपनी नई ताकत का श्रेय जनता के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को जाता है, जिन्होंने सत्ता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका नेतृत्व विपक्ष को करना चाहिए था। लोगों ने न केवल अपने वोट डाले, बल्कि सरकार के खिलाफ मोर्चा भी संभाला। वोट को प्रभावित करने वाले कारकों में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार और धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकता शामिल थे। जबकि शहरी मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर अधिक था, ग्रामीण मतदाताओं ने विपक्षी गठबंधन का भारी समर्थन किया।

लेख पर एक नज़र

2024 के भारतीय चुनावों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया गया और एकता, न्याय और प्रगति को अपनाया गया। चुनाव परिणामों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नफरत की राजनीति, संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग और बड़े व्यवसाय के पक्ष में नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया।

ष्ठ्रश्ँ गठबंधन की जीत का श्रेय किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और नागरिक समाज के समर्थन को दिया गया। लोगों ने नफ़रत, तानाशाही और सांप्रदायिकता की राजनीति को नकार दिया और इसके बजाय अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को चुना।

चुनाव परिणामों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से निपटने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर किया। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन चुनाव परिणाम जनता की आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्र को आकार देने का एक आशाजनक अवसर प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश में मतदाताओं ने नफरत की राजनीति को नकार दिया और भगवा पार्टी की मंदिर-मस्जिद राजनीति के महाकेन्द्र अयोध्या में भी भाजपा को चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा। यह नफरत और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को सीधा झटका था। महाराष्ट्र में यह झटका इसलिए लगा क्योंकि मतदाताओं ने जोड़-तोड़ और दबाव वाली राजनीतिक प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें विपक्षी दलों को तोड़ना और ऐसा करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना भी शामिल था।

परिणामों और उनके निहितार्थों के विश्लेषण से पता चलता है कि लोगों को एक पार्टी, एक नेता, एक भाषा, एक धर्म की अवधारणा अस्वीकार्य लगी है। उन्होंने राजनीति के बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है और पुष्टि की है कि भारत कई धर्मों, संस्कृतियों और विविधताओं का देश है, और देश पर केवल आम सहमति से ही शासन किया जा सकता है।

चुनाव परिणाम मोदी सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद की गई कुछ बड़ी गलतियों के खिलाफ एक स्पष्ट फैसला था। पहली थी नफरत की विभाजनकारी राजनीति, जिसने कुछ समुदायों को अलग-थलग करने और उन्हें कलंकित करने की कोशिश की। इसमें समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर डालना और परेशान करना, ज़हरीले आख्यान फैलाना और सामाजिक बंधनों को तोड़ना शामिल था। विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), चुनाव आयोग और अदालतों जैसी संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करना दूसरी गलती थी। इससे कम नहीं, देश की संपत्ति को चंद लोगों के हाथों में केंद्रित करने वाले क्रोनी पूंजीवाद को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया।

भाजपा के कुशासन के खिलाफ संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पांच प्रमुख राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु - ने निभाई, जिनमें कुल मिलाकर 249 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों में मतदाताओं ने नफरत की राजनीति को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया, जिससे पार्टी के प्रभुत्व को बड़ा झटका लगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा को भारी झटका लगा है, फिर भी किसी भी तरह की लापरवाही से सावधान रहना होगा क्योंकि विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। विपक्ष को लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने और शांति और सद्भाव का माहौल बनाने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है।

भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर 2024 के आम चुनावों के परिवर्तनकारी प्रभाव ने देश के मतदाता समुदाय के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है। चुनाव परिणाम भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से गरीब समुदाय के लिए एक शानदार सफलता रही है।

राजनीति का मतलब राज्य की नीति को प्रभावित करना है, न कि सिर्फ़ सांसदों का चुनाव करना। लोकतांत्रिक समाजों में लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, जो बदले में शासन और राज्य की नीति निर्माण के लिए सकारात्मक एजेंडा तैयार करता है।

चूंकि हम इस वर्ष चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हैं, इसलिए इन संसदीय चुनाव परिणामों से उत्पन्न गति को बनाए रखने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।

आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने देश को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आकार देने का एक आशाजनक अवसर प्रदान किया है। सभी हितधारकों - सरकार, विपक्षी दल और नागरिक समाज - को मतदाताओं की आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए और एक सच्चे लोकतांत्रिक, समावेशी और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। (लेखक - प्रो प्रदीप माथुर/ईएमएस) (लेखक मीडिया मैप वेबसाइट (स्र्ॅ्ज़्म्द्.ग्ह) के मुख्य सम्पादक है।)

चले चलो! आज धनवान की शादी है

जो लोग 500 वर्ष बाद भगवान राम के मंदिर , प्राण प्रतिष्ठा समारोह उत्सव में नहीं आये, मुँह फुलाकर कैकेई और मंथरा बने रहे , वही लोग आज अम्बानी के पुत्र के विवाह में दौड़े चले गए।

शास्त्र के नाम पर पल पल बखेड़ा खड़ा करने वाले लोग जिन्होंने अशास्त्रीय मानकर और शास्त्र की आड़ लेकर अपने अहंकार में को पोषित करने का कुचक्र किया था, आज वही लोग सन्यासी होकर भी विवाहोत्सव में चले गए।

पैसा सबको नचा देता है। इन लोगों को राम मंदिर से ज्यादा अपनी कीर्ति प्यारी थी।

अब कृपा कर यह समस्त हिन्दू समाज को बतायें कि कौन से शास्त्र के अनुसार यह लोग सन्यासी होकर विवाहोत्सव में गए?

क्या यह राम मन्दिर से बढ़ कर था ?

चलिए गृहस्थ सन्तों की बात अलग है, उनको यह निषेध नहीं है।

लेकिन यह बहुत बड़े पीठाधीश अवश्य बतायें कि सन्यासी होकर यह किस शास्त्र विधि का पालन करके गए?

सन्यासियों के लिए तो यह नियम है कि एक गाँव में एक ही रात ठहरने का नियम होता है , इससे ऊपर वह एक गाँव में निवास नहीं कर सकते अपने आश्रम को छोड़कर।

सन्यासी के चार भेद होते हैं।

1. कुटिचक
2. बहुदक
3. हंस
4. परमहंस

इन चारों के नियम के अनुसार कृपया सभी सनातन धर्मियों को बताएं कि वह किस शास्त्र के नियम से विवाहोत्सव में गए?

अरे सन्यासियों को तो नर्म गद्दा , रुई , अग्नि , धातु पात्र तक प्रयोग में लाना चाहिए।

जब आप शास्त्र शास्त्र करके समाज को तोड़ते हैं , तब तो आप को भी शास्त्र के नाम पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए ।

यह सनातन धर्मी सब देख रहा है आप लोगों का।

इस कलियुग में जितना आडंबर और पाखंड फैला है न , वह सब दृष्टिगोचर हो रहा है।

स्वयं के लिए कोई नियम नहीं और वैसे चींटी तक के लिए शास्त्र शास्त्र कर के नियम बिना सिर पैर के करेंगे इसीलिए कलियुग के लक्षणों में यह लिखा है कि जब भगवान कल्कि अवतार में आएंगे तो सबसे पहले आश्रमों को नष्ट करेंगे क्योंकि कलियुग के प्रभाव से अधर्म धर्म को चोला पहन कर इन आश्रमों में वास करने लगेगा।

हम सनातन धर्मी आपसे यह प्रश्न तब न पूछते जब आप हमारे आराध्य भगवान श्री रामचन्द्र के उत्सव में सम्मिलित होकर हम सभी जनों को अपना आशीर्वचन प्रदान करते और समस्त विश्व को यह संदेश देते कि हम सनातन धर्मी एक हैं।

तब आपसे हम यह प्रश्न न पूछते लेकिन अब हमारा यह कर्तव्य है कि आपसे पूछें कि अब कहाँ फेंक दिए आपने सारे शास्त्र? कहाँ गया सन्यासी का नियम ? कहाँ गयी पीठ की मर्यादा? कहाँ गयी आचार्य शंकर की वह मर्यादा जिसका नाम ढोकर और आगे लगाकर आप लोग यह अमर्यादित कृत्य कर रहे हैं?

हम अन्य किसी सन्त और साधु को नहीं कहेंगे क्योंकि वह भगवान श्रीरामचन्द्र के इस शताब्दी के सबसे बड़े महोत्सव में सम्मिलित हुए थे और प्रसन्नतापूर्वक सभी सनातन धर्मियों को अपना आशीर्वाद दिया था।

लेकिन आप लोगों पर आद्य जगद्गुरु आचार्य शंकर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का यह आरोप सदा लगता रहेगा। (लेखक- संजय गोस्वामी/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8075

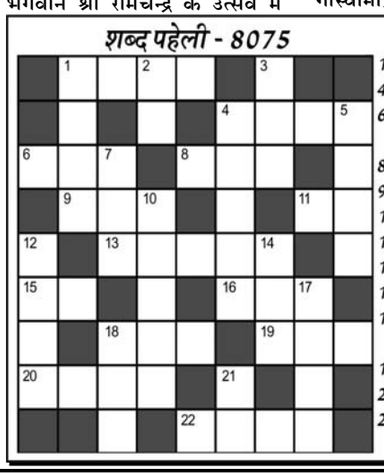

बाएँ से दाएँ

1. खटपट, ठनाठनी-4
4. पंजाब की एक नदी-4
6. चित्रकमेल, लम्बी गर्दनवाला पशु-3
8. दंड, दम, शामन-3
9. धरा, भूमि-3
11. शासन व्यवस्था, रहस्य-2
13. नवचंद्राकार-5
15. अकेला-2
16. दया, करुणा-3
18. बंदर का खेल दिखाने वाला-3
19. देवर्षि, देवमुनि-3
20. सब्जी, भाजी-4
22. कुंए पर पानी भरने का चबूतरा-4

ऊपर से नीचे

1. गुनाह, दोष, जुर्म-3
2. अपराधमुक्त, निवृत्त-2
3. सौत, दूसरी स्त्री-3
4. होशियार, गुणवान-5
5. भूकम्प-4
7. भेद, तुलना-3
10. परिचर्या-5
12. स्वभाव-4
14. स्थित होना-3
17. श्मशान-4
18. गृह, भवन-3
21. जीवन, जीव, स्फूर्ति-2

शब्द पहेली -8074 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

रुस की दोस्ती का बदला ले रहा अमेरिका, भारत को नहीं दे रहा तेजस के इंजन

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका कोई भी फैसला बिना किसी लाभ के नहीं करता है। ऐसा ही कुछ वह भारत के साथ कर रहा है। इसका असर रक्षा संबंधों में भी देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, भारत को तेजस में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक एफ404 इंजन देने में जानबूझ कर देरी कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि भारत रुस का बहुत अच्छा दोस्त है और हाल ही में पीएम मोदी रुस की यात्रा पर भी गई थे। वहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया था। इन सब बातों को लेकर वह भारत से बदलना लेना चाहता है। इंजन की डिलीवरी में देरी के कारण भारत में ही बनने वाले स्वदेशी तेजस एमके-1ए लाइन के उत्पादन में कमी आ रही है। इससे भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन बेड़े की ताकत को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका, भारत के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस के लिए जेट इंजन की आपूर्ति में पिछड़ता है तो अमेरिकी विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी और अनुबंध को खत्म भी किया जा सकता है। रिटायर्ड एयर मार्शल एम. माथेस्वरन ने कहा कि अमेरिकी एफ404 इंजन की आपूर्ति में देरी से भारतीय वायुसेना पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तेजस एमके1 और तेजस एमके1ए के छह स्क्वाड्रन जल्द ही सर्विस में शामिल होने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना में पहले से ही स्क्वाड्रन की समस्या है। वर्तमान में, भारतीय वायुसेना 45 की जरुरत के मुकाबले 32 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यहां-वहां थोड़ी-बहुत देरी से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तेजस लड़ाकू विमान के अगली पीढ़ी के एमके2 संस्करण को शक्ति प्रदान करने वाले एफ414 इंजन भारत को मिलने चाहिए और यदि अमेरिकी ऐसा नहीं करता हैं, तो अनुबंध खतरे में पड़ जाएगा।

माथेस्वरन ने कहा कि अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि अमेरिका से भारत आने वाले किसी भी सैन्य उपकरण के बारे में हमेशा अविश्वास और विश्वसनीयता की कमी की भावना रही है। हालांकि उसने पिछले 15 सालों में भारत के साथ बड़े रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अमेरिकियों को अधिक विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि देरी इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए अनुकूल नहीं होगी।

खेल - समाचार

महिला एशिया कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को सात विकेट से हराया

दांबुला (ईएमएस)। श्रीलंकाई टीम ने महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश को सात विकेट से हरा दिया। इस मैच में में बांग्लादेश की महिलाओं ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 111 रन बनाये। इसके बाद श्रीलंकाई टीम ने जीत के लिए मिले 112 रनों के लक्ष्य को विश्मी गुणारत्ने 51 और हर्षिता समाराविक्रमा के 33 रनों की सहायता से आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने एक समय 1.3 ओवर में ही 17 रनों पर अपने 4 विकेट खो दिए थे।

दिलारा अख्तर 6 जबकि इश्मा तंजीम और रुब्या हैदर अपना खाता नहीं खोल पायीं। ऋतु मोनी 3 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना ने शोरिफा खातून के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। शोरिफा खातून 5 रन बनाकर आउट हुई। छठां विकेट राबेया खान 10 का गिरा। शोरना अख्तर ने 25 रन जबकि निगार ने सबसे अधिक 48 रन बनाये। श्रीलंका की ओर से उदेशिका प्रबोधनी और इनोशी प्रियदर्शिनी ने दो-दो विकेट लिए जबकि सुगंधिका कुमारी, कविशा दिलहारी और चमारी अट्टापटू ने एक-एक विकेट लिया।

श्रेयंका महिला एशिया कप से बाहर हुईं, तनुजा शामिल

दांबुला (ईएमएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोटिल होने के कारण एशिया कप से बाहर हो गयी हैं। श्रेयंका के बाएं हाथ में चोट लग गयी थी। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की ओर से कहा गया है कि श्रेयंका के बाएं हाथ की चौथी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे में श्रेयंका की जगह पर तनुजा कंवर को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दांबुला में पाकिस्तान महिला के खिलाफ पिछले मैच में श्रेयंका ने अच्छी गेंदबाजी की थी और दो विकेट लिए थे। ऐसे में उनका बाहर होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है।

महिला एशिया कप : भारतीय टीम ने यूएई को 78 रनों से हराया

दांबुला (ईएमएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को भी 78 रनों से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर 66 और ऋचा घोष 64 के अर्धशतकों की सहायता से 5 विकेट पर 201 रन बनाये। इस प्रकार यूएई को जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य मिला जिसका पीछा करते हुए यूएई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान

माइक्रोसॉफ्ट ने तैनात किए हजारों इंजीनियर और विशेषज्ञ

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने साइबर सुरक्षा भागीदार क्राउडस्ट्राइक की वजह से गड़बड़ी पैदा होने के बाद अपनी सेवाओं को बहाल करने के लिए सैकड़ों इंजीनियरों और विशेषज्ञ तैनात ?किए है। कंपनी ने एक ब्लॉग में यह जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार 18 जुलाई को क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण पैदा हुई दिक्कतों से दुनियाभर में 85 लाख उपकरण प्रभावित हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉग पोस्ट में कहा ?कि सेवाओं को बहाल करने के लिए ग्राहकों के साथ सीधे काम करने के लिए सैकड़ों माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरों और विशेषज्ञों को तैनात किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर पैदा हुई इस गड़बड़ी से कई बिक्री केंद्र प्रभावित हुए और यहां तक कि भारत में कई एयरलाइन कंपनियों की उड़ानें बंद हो गईं। इस रुकावट ने दुनियाभर में कंपनियों और प्रणालियों के परिचालन को पूरी तरह रोक दिया था। इसकी वजह से हवाई अड्डे और एयरलाइन परिचालन में व्यवधान आया। एयरलाइन कंपनियों को अपने यात्रियों के लिए परामर्श जारी करना पड़ा। इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा के नेटवर्क पर ऑनलाइन चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में व्यवधान आया, जिससे उन्हें मैनुअल तरीके से चेक-इन का काम करना पड़ा। कई उपयोगकर्ताओं ने गड़बड़ी पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर व्यवधान की सूचना दी और कई ने एक्स पर संदेश जारी कर अपनी निराशा जताई। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह गूगल क्लाउड मंच (जीसीपी) और अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) सहित अन्य क्लाउड प्रदाताओं और हितधारकों के साथ सहयोग कर रही है, ताकि उद्योग जगत को बताया जा सके कि इसका प्रभाव क्या रहा। साथ ही क्राउडस्ट्राइक और ग्राहकों के साथ बातचीत को भी साझा किया जा सके। ब्लॉग में कहा गया है ?कि हम इस समस्या के कारण कारोबार क्षेत्र और कई व्यक्तियों की दैनिक दिनचर्या में आए व्यवधान की पहचान कर रहे हैं। हमारा ध्यान बाधित प्रणाली को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन वापस लाने के लिए ग्राहकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने पर है।

खुदाई में 4 हजार साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले,वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीजें मिली

लंदन (ईएमएस)। भूमध्य-सागर में बने एक आइलैंड में वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीजें मिली हैं। सिपरस में जमीन की खुदाई में 4 हजार साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। सिपरस में मौजूद इस आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम एरिमी है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना के लूका बॉम्बार्डियरी इस प्रोजेक्ट के हेड थे।

प्रोजेक्ट को सिपरस के डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्स के साथ मिलकर पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि हाल की खुदाई से एक पुराना और पवित्र मंदिर मिला है जिसके धार्मिक और वैचारिक रूप से काफी महत्व लग रहा है।उन्होंने बताया कि कांस्य-युग के मध्य (2000-1600 ईसा पूर्व) में कारीगरों ने तय किया कि वो एरिमी हिल पर बसेंगे और समुदाय के लिए रहने योग्य एक जगह का निर्माण करेंगे, जिसकी कई प्रकार की विशेषताएं होंगी। इस स्थान के एक भाग में टीम को एक कमरा मिला, जिसमें एक रहस्यमयी पत्थर मौजूद था जो करीब 7 फीट ऊंचा है। इस ढांचे को कायदे से पॉलिश किया गया था।

शोधकर्ताओं ने बताया कि मोनोलिथ पहले कमरे के बीच में रखा रहा होगा, जो जमीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से नीचे पड़ा मिट्टी का एक मटका चूर-चूर हो गया था। ये कमरा वैज्ञानिकों को काफी पवित्र स्थान लगा, जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। एक युवती की टूटी हुई खोपड़ी भी कमरे में मिली और उसके सीने के ऊपर एक भारी पत्थर रखा गया था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे हिलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस लड़की को प्रेग्नेंसी की वजह से मारा गया होगा।

133 मौत और 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव

बांग्लादेश में अब 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां मेरिट पर

ढाका(ईएमएस)। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच 133 लोगों की मौत और 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आरक्षण की इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को अवैध माना है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में सरकारी नौकरियों में 93 फीसदी पद मेरिट के आधार पर भरने का आदेश दिया, वहीं 1971 मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों और अन्य श्रेणियों के लिए सिर्फ 7 प्रतिशत पद आरक्षित रखने को कहा।

बांग्लादेश में अब चले आ रहे कोटा सिस्टम के तहत 56 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित थीं। इनमें से 30 प्रतिशत 1971 मुक्ति संग्रामके सेनानियों के वंशजों के लिए, 10 प्रतिशत पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10 प्रतिशत महिलाओं के लिए, 5 प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1 प्रतिशत विकलांग लोगों के लिए आरक्षित थीं। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30 फीसदी आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलनरत हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हर साल करीब 3 हजार सरकारी नौकरियां ही निकलती हैं, जिनके लिए करीब 4 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं।

साल 2018 में इस कोटा सिस्टम के विरोध में बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन हुआ था। शेख हसीना सरकार ने तब कोटा सिस्टम को निलंबित करने का फैसला किया था। मुक्ति संग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पिछले महीने शेख हसीना सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और कोटा सिस्टम को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, बसों और ट्रेनों में आगजनी की। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हसीना सरकार को सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी।

विदेशी निवेशकों ने 19 जुलाई तक शेयरों में 30, 772 करोड़ का निवेश किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। नीतिगत सुधार जारी रहने की संभावना, लगातार आर्थिक वृद्धि और कंपनियों के तिमाही नतीजे अच्छे रहने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 30,772 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बाजार के जानकारों ने कहा ?कि इसके अलावा बजट के सुधारोन्मुख रहने की उम्मीद से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। आगे चलकर यदि डॉलर और बॉन्ड प्रतिफल में नरमी का हालिया रुख जारी रहता है, तो एफपीआई की भारतीय बाजार में लिवाली जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि घरेलू और विदेशी निवेशक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संभावित बदलावों पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने इस महीने 19 जुलाई तक शेयरों में 30,772 करोड़ रुपये डाले हैं। इससे पहले राजनीतिक स्थिरता और बाजारों में तेज उछाल के कारण जून में उन्होंने शेयरों में 26,565 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वहीं इससे पहले एफपीआई ने चुनावी नतीजों को लेकर असमंजस के बीच मई में शेयरों से 25,586 करोड़ रुपये निकाले थे। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि की चिंता के बीच अप्रैल में उन्होंने 8,700 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी। समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने शेयरों के अलावा ऋण या बॉन्ड बाजार में 13,573 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे इस साल अब तक बॉन्ड बाजार में उनका निवेश 82,197 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

बारिश से आपूर्ति प्रभावित होने से दिल्ली में टमाटर 100 रुपए किलो बिका

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में बारिश की वजह से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने से शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक ?बिक गया। दिल्ली में मदर डेयरी के खुदरा बिक्री केंद्र सफल पर टमाटर 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 93 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई को टमाटर का अखिल भारतीय औसत मूल्य 73.76 रुपये प्रति किलोग्राम था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्यधिक गर्मी और उसके बाद अत्यधिक बारिश से आपूर्ति में व्यवधान के चलते पिछले सप्ताह कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अधिकारी ने बताया ?कि दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अत्यधिक गर्मी और उसके बाद अत्यधिक बारिश के कारण आपूर्ति बाधित हुई, जिससे खुदरा कीमतों में उछाल आया।

पश्चिमी दिल्ली में मदर डेयरी स्टोर पर शनिवार को प्याज 46.90 रुपये प्रति किलोग्राम और आलू 41.90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जा रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज 50 रुपये प्रति किलोग्राम और आलू 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा है। प्याज का अखिल भारतीय औसत मूल्य 44.16 रुपये प्रति किलोग्राम और आलू का औसत मूल्य 37.22 रुपये प्रति किलोग्राम है।

हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं। मदर डेयरी में शनिवार को तोरी 59 रुपये प्रति किलो, करेला 49 रुपये प्रति किलो, फ्रेंच बीन्स 89 रुपये प्रति किलो, भिंडी 49 रुपये प्रति किलो, टिंडा 119 रुपये प्रति किलो, हरी शिमला मिर्च 119 रुपये प्रति किलो, बैंगन (छोटा) 49 रुपये प्रति किलो, बैंगन (बड़ा) 59 रुपये प्रति किलो, परवल 49 रुपये प्रति किलो, लौकी 39 रुपये प्रति किलो और अरवी 69 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रही थी।

गाजा के बाद इजराइल का अब यमन पर हमला

हूती के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

होदेइदा (ईएमएस)। हमास के खिलाफ जंग के 9 महीने बाद इजराइल ने पहली बार यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। इजराइल ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदैदा पोर्ट और पावर स्टेशन को निशाना बनाया। हमले के बाद एक फ्यूल डिपो में भीषण आग लग गई। सोशल मीडिया पर कई फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें धुएं का गुबार उठते देखा गया है। इस हमले में 3 हूती विद्रोहियों की मौत हुई है, जबकि 87 लोग घायल हुए हैं। हालांकि, हमले की गंभीरता को देखते हुए यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

इजराइली ने तेल अवीव पर हमले के जवाब में यमन पर अटैक किया है। दरअसल, हूती विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइली शहर तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया था। इसमें एक 50 साल के इजराइली की मौत हो गई थी। वहीं करीब 10 लोग घायल हुए थे। इजराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद कहा कि इजराइली नागरिकों के खून की कीमत होती है और अगर इजराइलियों पर हमला हुआ, तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। गैलेंट ने कहा कि होदैदा में जो आग इस समय जल रही है, वह पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका मतलब साफ है।

रूस से समझौते को तैयार जेलेंस्की

कीव,(ईएमएस)। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अब रूस के साथ समझौता कर युद्ध विराम की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए शांति शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल भेजने और बातचीत करने के संबंध में इशारा किया है।

तेल ठिकानों पर की बमबारी, कई की मौत

यरूशलेम(ईएमएस)। इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने यमन में हौथी मिलिशिया से जुड़े ठिकानों पर बमबारी की है। एक दिन पहले ही हौथी सैन्य समूह ने इजरायल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला कर एक व्यक्ति को मार डाला था। यमनी हौथी सैन्य समूह ने दावा किया है कि इजरायली हमले में यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर होदेदाह में तेल भंडार और बिजली सुविधाओं को निशाना बनाया गया, और कई लोग मारे गए या घायल हुए हैं। हौथी समूह के अल-मसीरा टीवी ने शनिवार को ये जानकारी दी। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने हौथी मिलिशिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हाल के महीनों में इजरायल के खिलाफ किए गए कई हमलों के जवाब में यह हमला किया गया। इससे पहले हौथी के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद अब्दुलसलाम ने कहा था इजरायली हमले हौथी सैन्य समूह को इजरायली शहरों और जहाजों को निशाना बनाने से नहीं रोक पाएंगे। हौथियों ने कहा है कि तेल अवीव में शुक्रवार को किया गया ड्रोन हमला गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया था। इससे पहले, हौथियों ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नवंबर 2023 से लाल सागर और अदन की खाड़ी में इजरायल से जुड़े जहाजों पर कई हमले किये हैं। जवाब में, अमेरिकी-ब्रिटिश नौसैनिक गठबंधन ने समूह को रोकने के लिए हौथी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इससे हौथी के हमले में कोई कमी नहीं आई। होदेदाह 2014 से हौथी समूह के नियंत्रण में है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों से बाहर कर दिया है।

होदेदाह में स्थानीय लोगों ने कहा कि घटनास्थल पर काले धुएं मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने लाल सागर के पास के क्षेत्र की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद दमकल गाड़ियां और एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गईं।

विदेशी निवेशकों ने 19 जुलाई तक शेयरों में 30,772 करोड़ का निवेश किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। नीतिगत सुधार जारी रहने की संभावना, लगातार आर्थिक वृद्धि और कंपनियों के तिमाही नतीजे अच्छे रहने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 30,772 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बाजार के जानकारों ने कहा ?कि इसके अलावा बजट के सुधारोन्मुख रहने की उम्मीद से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। आगे चलकर यदि डॉलर और बॉन्ड प्रतिफल में नरमी का हालिया रुख जारी रहता है, तो एफपीआई की भारतीय बाजार में लिवाली जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि घरेलू और विदेशी निवेशक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संभावित बदलावों पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने इस महीने 19 जुलाई तक शेयरों में 30,772 करोड़ रुपये डाले हैं। इससे पहले राजनीतिक स्थिरता और बाजारों में तेज उछाल के कारण जून में उन्होंने शेयरों में 26,565 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वहीं इससे पहले एफपीआई ने चुनावी नतीजों को लेकर असमंजस के बीच मई में शेयरों से 25,586 करोड़ रुपये निकाले थे। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि की चिंता के बीच अप्रैल में उन्होंने 8,700 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी। समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने शेयरों के अलावा ऋण या बॉन्ड बाजार में 13,573 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे इस साल अब तक बॉन्ड बाजार में उनका निवेश 82,197 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

महिलाओं को फोन कर बुलाता फिर कर देता बेरहमी से हत्या, अब तक 42 की हत्या की

नैरोबी,(ईएमएस)। केन्या की राजधानी नैरोबी में सीरियल किलर के घर से अजीबो गरीब चीजें बरामद हुई हैं। वहीं सीरियल किलर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है जो सुनने के बाद होश उड़ जाएंगे ओर डर लगने लगेगा है।

पुलिस के मुताबिक कॉलिन्स जुमैसी खालुशा को लोग पिशाच कहते हैं। 33 साल के इस आरोपी ने अब तक कम से कम 42 महिलाओं की बेरहमी से हत्या की है जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। वह हत्या के बाद महिलाओं के शव की दुर्दशा कर देता था और फिर उसे नाइलॉन की बोरी में पैककर देता था। आरोपी पुलिस थाने के पास स्लम क्षेत्र में इन लाशों को फेंक देता था। तलाशी के दौरान उसके घर से बांका, रबर के दस्ताने, सेलोटेप और लाइलॉन की बोरी मिली है।

केन्या में इस समय लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। ऐसे में विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने इस तरह के मामले को तूल दे रही है। नैरोबी के एक स्लम में जब नौ कंकाल मिले तब छानबीन शुरू हुई। यहां स्थानीय लोग कूड़ा फेंकते थे। उसमें खालुशा शवों को फेंक जाता था। इसके बाद पास ही रहने वाले खालुशा ने माना कि वह महिलाओं को लालच देता है और फिर उनकी हत्या कर फेंक देता था।

खालुशा ने 2022 से अब तक 42 महिलाओं की हत्या की जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। खालुशा के घर से पुलिस को कई सारे मोबाइल फोन, आई कार्ड. नाइलॉन के बोरे मिले हैं। खालुशा की शिकार हुई महिलाओं में 26 साल की जोसेफीन ओविनो भी थीं। एक दिन उन्हें एक फोन आया और इसके बाद वह लापता हो गईं। उनकी बहन पेरिस केया ने उनको ढूंढना शुरू किया और फिर पता चला कि कूड़े के ढेर पर उनका शव मिला था।

फॉरेंसिक जांच में पता चला कि कूड़े में ज्यादातर शवों के धड़ मौजूद थे लेकिन सिर गायब थे। केवल एक का पूरा शव मिला था। किसी भी शव पर गोलियों के निशान नहीं थे। एक का गला दबाकर मारा। लोगों का कहना है कि इतने दिनों में पुलिस एक भी लापता महिला की तलाश नहीं कर पाई और ना ही सीरियल किलर के बारे में पता लगा पाई। वहीं जहां शव फेंके जाते थे वह जगह पुलिस स्टेशन के पास ही है। खालुशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर गौर करना चाहिए।

खुदाई में 4 हजार साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले,वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीजें मिली

लंदन (ईएमएस)। भूमध्य-सागर में बने एक आइलैंड में वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीजें मिली हैं। सिपरस में जमीन की खुदाई में 4 हजार साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। सिपरस में मौजूद इस आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम एरिमी है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना के लूका बॉम्बार्डियरी इस प्रोजेक्ट के हेड थे।

प्रोजेक्ट को सिपरस के डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्स के साथ मिलकर पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि हाल की खुदाई से एक पुराना और पवित्र मंदिर मिला है जिसके धार्मिक और वैचारिक रूप से काफी महत्व लग रहा है।उन्होंने बताया कि कांस्य-युग के मध्य (2000-1600 ईसा पूर्व) में कारीगरों ने तय किया कि वो एरिमी हिल पर बसेंगे और समुदाय के लिए रहने योग्य एक जगह का निर्माण करेंगे, जिसकी कई प्रकार की विशेषताएं होंगी। इस स्थान के एक भाग में टीम को एक कमरा मिला, जिसमें एक रहस्यमयी पत्थर मौजूद था जो करीब 7 फीट ऊंचा है। इस ढांचे को कायदे से पॉलिश किया गया था।

शोधकर्ताओं ने बताया कि मोनोलिथ पहले कमरे के बीच में रखा रहा होगा, जो जमीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से नीचे पड़ा मिट्टी का एक मटका चूर-चूर हो गया था। ये कमरा वैज्ञानिकों को काफी पवित्र स्थान लगा, जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। एक युवती की टूटी हुई खोपड़ी भी कमरे में मिली और उसके सीने के ऊपर एक भारी पत्थर रखा गया था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे हिलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस लड़की को प्रेग्नेंसी की वजह से मारा गया होगा।

आखिरी ईएमआई का किया भुगतान फिर भी कर्ज बाकी!

- हाई कोर्ट ने बैंक, केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली (ईएमएस)। एक दंपती ने घर के लोन की आखिरी ईएमआई देकर सोचा ?कि अब घर का सारा कर्ज चुका ?दिया गया है। लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब बैंक प्री-क्लोजर स्टेटमेंट में लाखों का कर्ज बकाया होने का दस्तावेज उनके सामने ले आया। इसे कारोबार का अनुचित तरीका बताते हुए दंपती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर संबंधित बैंक और उसके एमडी के साथ केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा गया है। जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने माया देवी और उनके पति की याचिका पर प्रतिवादी बैंक पीरामल फाइनेंस और उसके सीएमडी को नोटिस जारी किया। केंद्र और आरबीआई से भी जवाब मांगा गया। मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि याची दंपती ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ आदेश पारित करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने इस बाबत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक शिकायत दी थी, जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक को भिजवाया गया, पर किसी ने अभी तक मामले में विचार नहीं किया है। एडवोकेट अमित कुमार के जरिए दायर याचिका में दंपती ने कहा कि उन्होंने रोहिणी में एक घर खरीदने के लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस से आठ लाख 65 हजार 386 रुपये का हाउसिंग लोन लिया था, जो 14 साल के लिए था। इसकी मासिक किश्त 8827 रुपये थी। 2021 में पीरामल ने दीवान हाउसिंग को टेकओवर कर लिया। दंपती ने दावा किया कि उन्होंने फरवरी 2024 में आखिरी ईएमआई भरने के साथ बैंक से अनुरोध किया वे उनके खाते को बंद कर दें और उनके घर के मुख्य दस्तावेज के साथ 'नो डयूज सर्टिफिकेट' जारी करे। पर उन्हें हैरानी तब हुई जब बैंक लोन प्री-क्लोजर स्टेटमेंट के साथ आया, जिसमें उन पर 5 लाख 58 हजार 284 रुपये बकाया होने की बात कहीं गई। आरोप लगाया कि इसके बाद बैंक के एजेंट, टेली कॉलर के जरिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगे। जो एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन्स, 2021 के खिलाफ है। इसके अलावा नैशनल हाउसिंग बैंक के फेयर प्रैक्टिस कोड का भी उल्लंघन करती है और याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों में दखल देती है।

खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग, आर्मी गो बैक के लगा रहे नारे

इस्लामाबाद,(ईएमएस)। पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी है। 10 हजार से ज्यादा पश्तून लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। इससे क्षेत्र में अशांति है और इसी वजह से आतंकी हमले हो रहे हैं। खैबर इलाके में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन को पश्तून बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता जमालुद्दीन वजीर ने कहा है कि इलाके में 20 साल से आतंकवाद खत्म करने की मुहिम के नाम पर पाकिस्तानी सेना लोगों पर जुल्म कर रही है।

प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है कि वे आतंकवाद <u>के नाम पर आम लोगों को परेशान</u> कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को आंदोलनकारियों के आर्मी कैंप घेरने पर सेना ने गोलीबारी की। इससे अब तक साता प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है। वहीं, 30 घायल हैं। अब आतंकी आत्मघाती हमलों के अलावा रिमोट कंट्रोल और ड्रोन से भी हमले कर रहे हैं। साल के शुरुआती 4 महीनों में 179 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ज्यादातर सेना और पुलिसवालों को टारगेट बनाया गया है। स्थानीय सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी लगा दी। सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है।

जर्मनी में अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की,पाकिस्तान का झंडा भी उतारा

बर्लिन (ईएमएस)। खालिस्तान समर्थकों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत अब अफगान नागरिक बन गए हैं। जर्मनी में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास पर अब अफगानों ने हमला बोल दिया है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अफगान नागरिकों ने वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की। साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी उतार ले गए। जर्मनी की पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी की हैं। इस घटना का वीडियो आया है, जिसमें दिख रहा है कि लोगों ने अफगानिस्तान तालिबान शासन आने से पहले का झंडा ले रखा है। वहीं इस घटना के बाद अफगानों का सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। वहीं प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान ने कराची में जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से यह बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अफगान नागरिकों का विरोध हो रहा है। वहीं हमले के पीछे का असली कारण पता नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने से लोग नाराज हैं। पाकिस्तान की एक टीवी होस्ट ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए अफगान नागिरकों के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि अगर सच में यह लोग इतने बहादुर हैं तो देश से भागने की जगह अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते, जैसे फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। जहां कई अफगान वाणिज्य दूतावास में घुसे और पाकिस्तानी झंडे को नीचे गिरा दिया। यह घटना अफगानों को खतरनाक, हिंसक, गैर-जिम्मेदार और अज्ञानी के रूप में दिखाती है। उन्होंने कहा ?कि इस तरह की कार्रवाइयां जर्मनी की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब पुलिस की गिरफ्तारी के बाद इन युवकों को पछतावा तो जरूर होगा, लेकिन इस पछतावे से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि इन कायरों में वास्तव में कोई गर्व होता तो वे अपमान के साथ भागने की जगह फिलिस्तीन के लोगों की तरह मातृभूमि के लिए लड़ते। इसकी जगह वे विदेशी दान पर जीने वाले मुफ्तखोर हैं। इस बीच पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह लगभग 15 लाख अफगान शरणार्थियों के पंजीकरण कार्ड का विस्तार करेगा।

निराशा को पीछे छोड़कर दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार है ये हॉकी खिलाडी

-दाहिना पैर पीठ की चोट के कारण अस्थायी रूप से हो गया था लकवाग्रस्त

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सुखजीत सिंह छह साल पहले की निराशा को पीछे छोड़कर 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक में टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करने को लेकर प्रतिबद्ध है। सुखजीत का दाहिना पैर पीठ की चोट के कारण अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गया था। भारत के लिए 2022 में पदार्पण करने वाले अग्रिम पंक्ति के इस खिलाड़ी ने हॉकी इंडिया से जारी विज्ञप्ति में कहा, 'ओलंपिक में खेलना हमेशा से मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सपना रहा है। यह किसी भी खिलाड़ी के करियर का शिखर है और मैं इस अवसर को पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि मेरी कड़ी मेहनत और समर्पण सफल होगी। मैं अपनी भूमिका को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के साथ पेरिस में अपना सब कुछ झोककर कोच और टीम के विश्वास पर खरा उतरने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं।

जालंधर में जन्मे सुखजीत ने पिता अजीत सिंह (पंजाब पुलिस के पूर्व हॉकी खिलाड़ी) से प्रेरित होकर छह साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। अच्छी शुरुआत के बावजूद सीनियर भारतीय टीम में उनकी राह आसान नहीं थी। सुखजीत को 2018 में सीनियर टीम के लिए मुख्य संभावित शिविर में शामिल किया गया था, लेकिन पीठ की गंभीर चोट के कारण उनका दाहिना पैर अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गया था। सुखजीत ने कहा, 'वह अवधि मेरे जीवन के सबसे कठिन समयों में से एक थी।

लगभग पांच महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। हॉकी खेलना तो दूर की बात है, मैं चल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, 'प्रत्येक दिन ऐसा महसूस होता था कि हॉकी खेलने का मेरा सपना दूर होता जा रहा था और यह काफी निराशाजनक था। सुखजीत ने कहा कि उनके परिवार, विशेषकर पिता के अटूट समर्थन से वह वापसी करने में सफल रहे। सुखजीत ने देश के लिए खेले गए 70 मैचों में 20 गोल करके अपनी प्रतिभा और निरंतरता को दर्शाया है। उन्होंने भुवनेश्वर में 2023 एफआईएच हॉकी विश्व कप में छह मैचों में तीन गोल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पिछले साल चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और हांगझोऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों का भी हिस्सा थे।

उन्होंने कहा, 'मेरे लिए पिछले दो साल शानदार रहे हैं। अब मेरा पूरा ध्यान प

सूरत शहर में रविवार शाम को भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव

मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी

सूरत : रविवार को शाम से शुरू हुई भारी बारिश ने सूरत शहर को चपेट में ले लिया। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी भर जाने से वाहन चालक फंस गए और यातायात बाधित हुआ।

सूरत सहित गुजरात के कई जिलों में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार को गिर सोमनाथ, दीव, अमरेली, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

सूरत शहर में उधना, लिंबायत, पांडेसरा, उधना दरवाजा, सहारा दरवाजा, वराछा गरनाला, नानपुरा, कादरशानी नाल, सलाबतपुरा, कतारगाम, सिंगणपोर, रांदेर, अडाजण समेत कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों से निकलने में काफी मुश्किलें हुईं।

मौसम विभाग ने सूरत सहित गुजरात के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, सर्कुलेशन ऑफशोर ट्रफ और शीयर जोन के कारण राज्य में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में द्वारका में सबसे ज्यादा 148 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

एसएमसी ने लाखों की विदेशी शराब समेत दो शख्सों को पकड़ा, स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता आई सामने

वडोदरा (ईएमएस) स्टेट मोनिटरिंग सेल (एसएमसी) ने वडोदरा के भिलापुरा गांव के निकट लाखों की शराब समेत दो शख्सों को गिरफ्तार कर लिया। एसएमसी की इस कार्यवाही से फिर एक बार स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता सामने आ गई है। एसएमसी ने शराब, वाहन और नकदी समेत रु. 24.52 का माल-सामान जब्त किया है। जबकि चार लोगों को वांटेड घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक एसएमसी को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के चांदपुर की दुकान से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब कार में वडोदरा लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएमसी ने वडोदरा जिले के भिलापुरा गांव के निकट निगरानी बढ़ा दी। इस बीच सूचना के मुताबिक कार आते देख उसे रुकने का इशारा किया।

लेकिन ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। जिसके बाद एसएमसी की टीम ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बीच कुछ दूरी पर एक कार से दो लोग भागने में सफल हो गए। जबकि अन्य कारों को घेराबंदी कर ली गई। कार की तलाशी में काले रंग के कपड़े के नीचे छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। उपरोक्त एसएमसी टीम ने विदेशी शराब, नकदी, कार, मोबाइल और नकदी समेत रु. 24.52 लाख रुपये का माल-सामान जब्त कर लिया। साथ ही रजक अब्दुल मंसूरी, दिलीप महेंद्रभाई परमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि सलीम उर्फ बटको पठान, नीरव उर्फ नीलेश भरतभाई पटेल, राकेश और छोटाउदेपुर से शराब से भरी कार देने वाले अज्ञात व्यक्तियों को वांछित घोषित किया गया है।

सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज, हजारों मंगलसूत्र लौटाए

गृह राज्य हर्ष संघवी का दावा, सरकारी अधिकारी भी सूदखोरी के धंधे में लिप्त पाया जाता है तो नहीं बख्शे जाएंगे

सूरत : सूरत पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले महीने में 120 से अधिक मामले सामने आने के बाद, पुलिस ने 90 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 58 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज एक लोक दरबार में सूदखोरों के शिकारबने23लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज लौटाए। उन्होंने कहा, ठअगर कोई सरकारी अधिकारी या राजनेता भी सूदखोरीके धंधे में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूरत पुलिस ने कई लोक दरबार आयोजित कर लोगों से सूदखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाकर सूदखोरों के द्वारा किए गए शोषण के बारे में बताया। संघवी ने आश्वासन दिया कि पुलिस सूदखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहेगी।

संघवी ने बताया कि पिछले साल से सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हजारों मंगलसूत्र लौटाए गए हैं। उन्होंने कहा, ठसूदखोरी एक सामाजिक बुराई है और हम इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संघवी ने लव जिहाद के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि प्यार के रिश्ते को बदनाम करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि लव जिहाद के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए।

सौशष्ट में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त

गांधीनगर, २१ जुलाई ।

गुजशत के सौशष्ट इलाके में बीते दो दिन में हुई भारी वर्षा से द्वारिका गीर सोमनाथ जामनगर जूनागढ़ व पोरबंदर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बीते ४८ घंटे में २० से २६ इंच तक वर्षा होने के कारण द्वारिका पोरबंदर व जूनागढ़ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केले पोरबंदर में अब तक ४४ लोगों को बचाया गया है। ६०० लोग आश्रय घरों में रह रहे हैं।

गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बीते दो दिन में हुई भारी वर्षा से द्वारिका, गीर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़ व पोरबंदर में जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। बीते ४८ घंटे में २० से २६ इंच तक वर्षा होने के कारण द्वारिका, पोरबंदर व जूनागढ़ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

कई बाजार, सड़क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। मांडविया ने पोरबंदर पहुंचकर प्रशासन से शहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने शहत शिविरों में जाकर प्रभावितों को मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। वर्षा से सबसे अधिक बस यातायात प्रभावित हुआ। अकेले पोरबंदर में करीब सौ से अधिक बसों का परिचालन नहीं किया गया। रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी बह जाने से कई ट्रेन रद्द की गईं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा पोरबंदर से सांसद मनसुख मांडविया ने अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

ईएसआईसी अस्पताल निर्माण कार्य दिसंबर-2024 तक हो जाएगा: हेमंत पांडे क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई

सूरत :दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 'ईएसआई अधिनियम 1948' पर एक सेमिनार शुक्रवार को सरसाना, सूरत में आयोजित किया गया था। जिसमें गुजरात राज्य के ईएसआई कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय निदेशक हेमंत पांडे और ईएसआई कॉर्पोरेशन सूरत के प्रभारी उप निदेशक दीपक मलिक वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय मेवावाला ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा, ''संसद द्वारा पारित कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम 1948 स्वतंत्र भारत में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहला प्रमुख कानून था। ईएसआई अधिनियम कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। जरूरत के समय उनके स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण को सुनिश्चित करता है और अंततः कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।

सूरत शहर में ईएसआईसी का अस्पताल निर्माण कार्य शुरू हो गया है, इसलिए कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान दिसंबर-2024 तक किया जाएगा। अब कर्मचारी को ऑनलाइन क्लेम करके ईएसआईसी का लाभ कैसे मिल सकता है, इसकी पढ़ाई एक साथ करनी होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि दक्षिण गुजरात में पारडी, गुंदलाव, उमरगाम और सरीगाम के कर्मचारियों के लिए चार नई डिस्पेंसरियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने संशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों के बारे में जानकारी दी।

दीपक मलिक ने ईएसआईसी पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, 'ईएसआईसी पीएमजेएवाय के साथ जल्द ही एमओयू साइन होने वाला है। जिससे कर्मचारियों को फायदा होगा। पुराना जर्जरीत सलाबतपुरा शाखा अस्पताल का डिमोलिशन के तत्काल निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ईएसआई के व्हाट्सएप चैनल, उमंग ऐप का उपयोग करने और ईएसआई सदस्यों के आधार को एएए+ ऐप पर लिंक करने का सुझाव दिया।'

सूरत 462 वर्ग किमी का शहर बन गया है, जबकि ईएसआई की मुख्य सेवाएं 5 वर्ग किमी के दायरे में हैं, कर्मचारियों को इलाज के लिए दूर-दूर से छुट्टी लेकर जाना पड़ता है। यानी उधना, वराछा, अडाजण, पाल, वेसु, रांदेर, डिंडोली जैसे क्षेत्रों में नए अस्पताल शुरू करने और सभी मौजूदा अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती करने का प्रस्ताव रखा गया। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि ईएसआई का मुख्य अस्पताल, जनरल अस्पताल, पिछले नौ महीनों से बंद है इस लिए प्रत्येक कर्मचारी को सिविल अस्पताल भेजा जाता है। इससमस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए उच्चस्तर पर पेशकश की जा रही है।

इसके अलावा, ईएसआई जनरल अस्पताल वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, इसलिए सभी मरीजों को पांडेसरा अस्पताल भेजा जाता है, जहां शाम 5 बजे के बाद डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। जिसके कारण आपातकालीन सेवाएं बाधित होती हैं, इसके लिए उचित कदम उठाने का सुझाव दिया गया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष निखिल मद्रासी ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन चैंबर की श्रम कानून समिति के अध्यक्ष सोहेल सवानी ने किया। सेमिनार के प्रश्नोत्तरी सत्र में अतिथियों ने उपस्थित लोगों के सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया और उसके बाद सेमिनार का समापन किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु आश्रम बगदाणा के दर्शनार्थ उपस्थित रहे

गांधीनगर 21 जुलाई. 2024 :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भावनगर जिले में बगदाणा स्थित गुरु आश्रम में दर्शनार्थ उपस्थित रहे, जहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने बापा सीताराम के जयघोष के साथ मुख्यमंत्री का भावपूर्वक स्वागत व अभिवादन किया।

श्री पटेल ने संत श्री बजरंगदास बापा के आसन स्थल में नन्हीं बालिकाओं के साथ पूजा-अर्चना की और फिर बजरंगदास बापा के समाधि स्थल के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ध्यान मंदिर तथा मुख्य शिखरबद्ध मंदिर के दर्शन किए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शिखरबद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर से श्रद्धालुओं तथा भक्तों के सैलाब को संबोधित किया। उन्होंने समग्र राज्य एवं देश को गुरू पूर्णिमा के पावन अवसर की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर बजरंगदास बापा के चरणों में शीश झुकाने का अवसर वास्तव में सौभाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ''मैंने गुरु आश्रम के दर्शन के दौरान सबके मांगल्य के लिए प्रार्थना की है। मैंने अभ्यर्थना व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित गुजरात व विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ें।''

मुख्यमंत्री ने गुरु आश्रम के ट्रस्टी मंडल के साथ बैठक की। श्री पटेल के करकमलों से आश्रम की वेबसाइट्ट्ट्ट्ट्स्ज्त.दु की लॉन्चिंग की गई। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन तथा दान आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

इस अवसर पर विधायक सर्वश्री शिवाभाई गोहिल, गौतमभाई चौहाण, भीखाभाई बारैया, जिला कलेक्टर श्री आर. के. मेहता, जिला विकास अधिकारी श्री जी. एच. सोलंकी, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. हर्षद पटेल, प्रांत अधिकारी श्री इशिता मेर, अग्रणी सर्वश्री महेंद्रसिंह सरवैया, भरतभाई मेर, गुरु आश्रम की ओर से ट्रस्टी सर्वश्री योगेशभाई सागर, धीरूभाई बाबरिया, रणजीतसिंह चामारडी, मुकेशभाई पटेल, नीलेशभाई डोडिया, विनोदभाई गुजराती, रसिकभाई सागर, जनकभाई काछडिया उपस्थित रहे।

राज्य के नगरों-शहरों में बसे लोगों के ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करने वाला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का महत्वपूर्ण निर्णय

गांधीनगर 21 जुलाई. 2024:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के शहरी क्षेत्रों की सड़कों को वर्षा ऋतु के दौरान होने वाले नुकसान को देखते हुए सड़कों की रिपेयरिंग तथा रिसरफेसिंग के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का निर्णय किया है।

नगरों-शहरों में रहने वाले लोगों को अच्छी सड़कों की सुविधा के साथ सड़क सुरक्षा मिले तथा उनके ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि हो;ऐसा जनहितकारी उद्देश्य मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय आवंटन में रखा है।

राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा के कारण शहरों-नगरों की सड़कों को हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए नगर पालिकाएँ अभी से अग्रिम आयोजन कर सकें;इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह वित्तीय आवंटन एडवांस में करने का निर्णय किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह धन आवंटित किया है।

इस योजना के मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना घटक के तहत वर्ष 2024-25 के लिए शहरी विकास विभाग ने 400 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने 157 नगर पालिकाओं में रोड रिपेयरिंग-रिसरफेसिंग कार्य वर्षा ऋतु पूर्ण होते ही तत्काल शुरू हो सकें तथा अच्छी सुविधायुक्त सड़कें उपलब्ध हों;इसके लिए नगर पालिकाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार कुल 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुमति दी है।

तद्अनुसार;अ श्रेणी की 22 नगर पालिकाओं को 1-1 करोड़ रुपए, ब श्रेणी की 30 नगर पालिकाओं को 80-80 लाख रुपए, क श्रेणी की 60 नगर पालिकाओं को 60-60 लाख रुपए और ड श्रेणी की 45 नगर पालिकाओं को 40-40 लाख रुपए का प्रस्तावित आवंटन सड़क सुविधा कार्यों के लिए किया जाएगा।

इस मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 तक नगर पालिकाओं को सड़क मरम्मत एवं सुविधायुक्त सड़कों के लिए 810.95 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

गुजरात ने वर्ष 2023-24 में 689.5 मैट्रिक टन आम का निर्यात किया, पिछले 5 वर्षों में 2500 मैट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात

गांधीनगर 21 जुलाई. 2024 : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा है। कृषि फसलों के अलावा; गुजरात बागवानी फसलों के उत्पादन में भी अग्रसर है। इसमें भी आम और विशेष रूप से केसर आम के आम के त्पादन में गुजरात समग्र देश में शीर्षस्थ राज्य है। गुजरात की कृषि अर्थव्यवस्था में आम उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात के आम की विदेशों में भी बहुत मांग है। गुजरात कृषि उद्योग निगम (जीएआईसी) के डेटा के अनुसार वर्ष 2023-24 में गुजरात से 689.5 मैट्रिक टन आम का निर्यात किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्षों में गुजरात ने कुल 2500 मैट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात किया है।

गुजरात में बागवानी फल एवं फूल फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 4,49,389 हेक्टेयर है, जिसमें से 1,77,514 हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती की जाती है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में आम के लिए आम के पेड़ों की सबसे अधिक बुवाई वलसाड, नवसारी, गीर-सोमनाथ, कच्छ तथा सूरत जिलों में होती है। गुजरात का तालाला गीर का आम समग्र विश्व में सर्वाधिक विख्यात है, जिसकी गुणवत्ता के कारण उसे जीआई टैग यानी जिओग्राफिकल इंडीकेशन टैग भी प्राप्त हुआ है। गीर के अलावा; कच्छ में भी केसर आम की खेती की जाती है। केसर के अलावा; राज्य में मुख्य रूप से हाफुस, राजापुरी, तोतापुरी, सोनपरी आदि किस्मों के आम भी उगाए जाते हैं।

अहमदाबाद के बावळा में स्थापित गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में इस वर्ष लगभग 210 मैट्रिक टन केसर आम का इराडिएशन कर उनका विदेशों में निर्यात किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह इकाई गुजरात की पहली और भारत की चौथी यूएसडीए-एपीएचआईएस सर्टिफाइड इराडिएशन इकाई है। गुजरात के कृषि मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल के मार्गदर्शन में गत वर्ष भी यहाँ लगभग 2 लाख किलो से अधिक केसर आम का इराडिएशन कर उनका निर्यात किया गया था।

इस इकाई के स्थापित होने से पहले गुजरात के आम कृषकों को मुंबई जाकर केसर आम का इराडिएशन कराना पड़ता और फिर वे आम का निर्यात करते थे। इसमें आम खराब हो जाते और परिवहन खर्च में भी वृद्धि होती थी, परंतु बावळा में इराडिएशन प्लांट स्थापित होने से किसान अब अहमदाबाद में ही आम का गामा इराडिएशन करवा कर आम का निर्यात करते हैं और उनके उत्पाद का उन्हें उत्तम दाम भी मिलता है।

इंडो-इजराइल वर्क-प्लान के तहत गीर सोमनाथ जिले में तालाला में निर्मित सेंटर ऑफ एक्सेस सेंटर फॉर मैंगो में किसानों को आम की फसल के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा; किसानों को घनिष्ठ खेती एवं नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षण तथा इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने संबंधी तकनीकी जानकारी भी दी जाती है। अब तक 2601 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा लगभग 9,382 पौधों का पालन कर किसानों को उनका विक्रय किया गया है।

राज्य सरकार के बागवानी विभाग द्वारा आम उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को 15.29 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

आम की खेती करने वाले किसानों के आम के पुराने बगीचों या बाड़ियों, जिनकी उत्पादन क्षमता कम हो, का नवीनीकरण करने के लिए योजना बागवानी विभाग द्वारा लागू है। इस योजना के फलस्वरूप किसानों को आम के पुराने बगीचे और बाड़ी नवीनीकरण के बाद अच्छा उत्पादन देने लगे हैं।

इसके अलावा; बागवानी विभाग द्वारा किसानों के लिए विभिन्न सहायता योजनाएँ लागू हैं। इनमें आम फसल के लिए अति घनिष्ठ खेती से बोई फल फसलों, घनिष्ठ खेती से बोई फल फसलों के लिए, अधिक कृषि खर्च की फल फसलों के अलावा फल फसलों में सामान्य अंतर पर बोई फल फसल के लिए सहायता, बागवानी फसलों की बुवाई के लिए प्लांटिंग मटीरियल में 90 प्रतिशत सहायता, इसके अलावा; फल फसलों की बुवाई के लिए प्लांटिंग मटीरियल में विशेष सहायता दी जा रही है। बागवानी विभाग द्वारा आम किसानों को आम की बुवाई के लिए लगभग 15.29 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है।

गुजरात सरकार ने समय से पहले क्लास-1 अधिकारी को किया सेवानिवृत्त

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात सरकार अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों के हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने एक और अधिकारी की समय से पहले छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक पेटलाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पंकज बारोट को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया है। 20 जुलाई 2024 से तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है। इसका आदेश राज्य के नगर विकास एवं शहरी आवास विभाग ने दिया है। पंकज बारोट के खिलाफ विभागीय जांच, न्यायिक और आपराधिक कार्यवाही उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी।राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सरकारी काम में लापरवाही बरत रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनके खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक या न्यायिक कार्यवाही चल रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पेटलाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पंकज बारोट को समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी है।

सूरत में पहली बार संदिग्ध मामला, अब तक २७ बच्चों की मौत

अहमदाबाद, २१ जुलाई ।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को सूरत में पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। यहां एक स्लम एरिया में रहने वाली ११ साल की बच्ची को तेज बुखार और उल्टियां होने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया है। राजकोट में भी एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। दोनों बच्चों के सैंपल जांच के लिए पुणे प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

इस तरह चांदीपुरा वायरस के मामलों की कुल संख्या ७३ हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या २७ पर पहुंच गई है। फिलहाल ४१ मरीज अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हाल ही में वडोदरा के सयाजी अस्पताल में चांदीपुरा वायरस से एक और ४ साल के बच्चे की मौत हो गई थी। अभी तक इस वायरस का असर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता था, लेकिन अब यह अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। चांदीपुरा वायरस को लेकर सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर १०४ शुरू किया है, जिसमें इस वायरस के सभी मामलों में इलाज की जानकारी उपलब्ध होगी।

चांदीपुरा वायरस गुजरात के गांवों और शहरी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। यह वायरस खासतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। वहीं, इस वक्त गुजरात में बच्चों के डॉक्टर माने जाने वाले पीडियाट्रिक डॉक्टरों की क्या हालत है इसका चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति पर भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ३१ मार्च, २०२२ तक गुजरात में ३४४ बाल रोग विशेषज्ञ (बच्चों के डॉक्टर) की आवश्यकता थी। इसके लिए ७६ सीटें स्वीकृत की गई थीं। इनमें से केवल ३० डॉक्टरों के पद भरे गए हैं और अभी भी ४६ पद खाली हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि आवश्यकता के अनुरूप ३४४ बाल रोग विशेषज्ञ होने चाहिए। यानी जरूरत की तुलना में मौजूद डॉक्टरों की संख्या घटा दें तो ३१४ डॉक्टर हैं। रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ कर्मचारियों की भी भारी कमी है।

जामनगर जिले में अब तक चांदीपुरा वायरस के कुल ५ संदिग्ध मामले पाए गए और नमूने जांच के लिए भेजे गए। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है। इन पांच बच्चों में से दो बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और मृतक बच्चे समेत ३ और बच्चों की रिपोर्ट आनी बाकी है। धोल के जाएवा के चांदीपुरा और जामजोधपुर के सेठवाडाला के बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। फिलहाल दोनों बच्चों की तबीयत स्थिर है, जबकि अन्य दो मरीज वेंटिलेटर पर हैं।

शुरुआत में वायरस के नमूनों को परीक्षण के लिए पुणे भेजना पड़ता था और उस रिपोर्ट को प्राप्त करने में अधिक समय लगता था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग चांदीपुरा वायरस के सैंपल की जांच जीबीआरसी (गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर) में करेगा। सैंपल को पुणे नहीं भेजना पड़ेगा और जांच गांधीनगर में ही हो जाएगी, जिससे रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी।

इस वायरस का पहला मामला १९६५ में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुर में सामने आया था। इस वायरस से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके प्रभावित हुए थे। वायरस से रोगी मस्तिष्क ज्वर (एन्सेफेलाइटिस) का शिकार हो जाता है। वायरस मच्छरों और मक्खियों के काटने से फैलता है।

सीटेक्स-2024 को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया, दो दिन में 14 हजार से अधिक आगंतुक

सूरत :दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दक्षिण गुजरात चैंबर व्यापार और उद्योग विकास केंद्र और सूरत टेकमैक फेडरेशन ने संयुक्त रूप से 20, 21 और 22 जुलाई 2024 को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सरसाणा में सूरत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एंड कन्वेंशन सेंटर में 'सीटेक्स - सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो - 2024' आयोजित किया गया है। एक्सपो का सोमवार 22 जुलाई को अंतिम दिन है।

प्रदर्शनी में टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल एंसिलरी और मशीनरी, टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी, एयरजेट लूम्स, वॉटर जेट लूम्स, रैपियर लूम्स, इलेक्ट्रॉनिक जैक्वार्ड, डॉबी मशीन, वेलवेट वीविंग मशीन, सर्कुलर बुनाई, यार्न डाइंग, वार्पिंग मशीन, डिजिटल प्रिंटिंग मशीनरी, पोजिशन प्रिंटिंग शामिल हैं। मशीनें, विभिन्न मुद्रण स्याही, सिलाई मशीनें, फ़्यूज़िंग मशीनें और बड़ी संख्या में मशीनरी और सहायक उपकरण प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिन्हें कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों के प्रदर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

कल पहले दिन सीटेक्स एक्सपो में 5345 खरीदार और आगंतुक आए। आज दूसरे दिन 8780 क्रेताओं एवं आगंतुकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रकार, दो दिनों के दौरान कुल 14,125 खरीदार और आगंतुक सीटेक्स एक्सपो में आए, जिससे प्रदर्शकों और सूरत के पूरे कपड़ा उद्योग को बहुत लाभ होगा।

इन दो दिनों के दौरान देश के विभिन्न शहर जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भिवंडी, ठाणे, कोयंबटूर, दादरानगर हवेली, दिल्ली, गाजियाबाद, पानीपत, वडोदरा, औरंगाबाद, जोधपुर, चेन्नई, बोइसर, मेरठ, गुड़गांव, आगरा, कोटा, अजमेर, गांधीधाम , सांगली, वाराणसी, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, राजकोट, जेतपुर पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक, मथुरा, खंडवा, इरोड, लुधियाना, पाली, जामनगर, आनंद, पोरबंदर, आगंतुकों ने सीटेक्स प्रदर्शनी का दौरा किया।

प्रतिकूल मौसम के बीच भारतीय कोस्ट गार्ड ने बीमार व्यक्ति का रेस्क्यू किया

पोरबंदर (ईएमएस) गुजरात में खासकर सौराष्ट्र में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। सौराष्ट्र के पोरबंदर, देवभूमिक द्वारका, गिर सोमनाथ समेत कई जिले मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो चुके हैं। इस बीच पोरबंदर के निकट जहाज में फंसे एक बीमार शख्स ने भारतीय कोस्ट गार्ड ने विपरीत परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। पोरबंदर से करीब 60 नोटिकल माइल दूर बीच समुद्र में एक व्यक्ति की तबियत बिगड़ गई थी। समुद्र में तेज हवा और भारी बारिश भी हो रही थी।

विजिबिलिटी भी 100 मीटर से भी कम थी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फंसे बीमार शख्स को हेलिकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। बीमार शख्स को बास्केट में बिठाया गया और उस बास्केट को हेलिकॉप्टर के जरिए उठाया गया और समुद्र से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने एस1 पोर्टफोलियो पर 25,000 रुपये तक की बचत के साथ आकर्षक डील्स पेश कीं

ओला एस1 एक्स+ का मूल्य स्टॉक रहने तक 10,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 84,999 रुपये से शुरू होगा।

बैंगलुरू, 19 जुलाई, 2024: ओला इलेक्ट्रिक अपने ओला एस1 स्कूटरों की खरीद पर 25,000 रुपये तक के आकर्षक बेनेफ़िट्स प्रदान कर रहा है। 22 जुलाई तक लागू इन ऑफरों में एस1 एक्स+ पर 10,000 रुपये और एस1 प्रो एवं एस1 एयर पर 5,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है। इन ऑफ़रों के अलावा ग्राहकों को ईएमपीएस 2024 के अंतर्गत 10,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। इन आकर्षक ऑफ़रों का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कीमतें बढ़ने से पहले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदकर उसे रजिस्टर कराना होगा।

ओला इलेक्ट्रिक एक विशाल एस1 पोर्टफोलियो पेश करता है, जिसमें आकर्षक मूल्य में छः उत्पाद हैं, जो विभिन्न रेंज की जरूरत वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हाल ही में कंपनी ने मास-मार्केट सेगमेंट में अपना एस1 एक्स पोर्टफोलियो उतारा है। तीन बैटरी कॉन्फिगुरेशन (2 किलोवॉटघंटा, 3 किलोवॉटघंटा, और 4 किलोवॉटघंटा) के साथ इन स्कूटरों का मूल्य क्रमशः 74,999 रुपये; 85,999 रुपये और 97,499 रुपये है। साथ ही इसके प्रीमियम स्कूटरों में एस1 प्रो, एस1 एयर, और एस1 एक्स+ का मूल्य क्रमशः 1,28,999 रुपये, 1,01,499 रुपये और 84,999 रुपये है।

ओला इलेक्ट्रिक अपने उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के 8 साल/80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड बैटरी वॉरंटी प्रदान करता है। ओला इलेक्ट्र